मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष निधि

404. **श्री अजीत जोगी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई परियोजनाओं को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए कोई विशेष निधि स्थापित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस निधि से मध्य प्रदेश को कोई धनराशि दी गयी है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली और अन्य नगरों को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए गैर-सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध

405. **श्री अजीत जोगी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और अन्य नगरों को प्रदूषणमुक्त रखने तथा पेट्रोल और डीजल की बचत करने के लिए गैर-सरकारी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के बारे में भी इस प्रकार की कोई योजना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

दूरसंचार विभाग की "विक्रम" परियोजना के उद्देश्य

406. **श्री अजीत जोगी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार विभाग की "विक्रम" परियोजना के क्या उद्देश्य हैं ;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या इस परियोजना की आवश्यकताएं स्वदेशी प्रौद्योगिकी से पूरी की जा सकती हैं ; और

(घ) यदि, नहीं, तो क्या सरकार इस परियोजना के लिए किसी उपकरण का आयात करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) "विक्रम" परियोजना का उद्देश्य डाटा संचार प्रदान करने के लिए एक पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क की स्थापना करना है ।

(ख) 1989 में "विक्रम" परियोजना के लिए आयातित उपस्कर की अनुमानित पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत 13.87 करोड़ रुपए थी ।

(ग) और (घ) पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क की स्थापना दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया है । पहले चरण में देश में ही उपलब्ध स्विचों की छोटी क्षमता का प्रयोग किया जाना है । नेटवर्क के दूसरे चरण में उक्त नेटवर्क का बड़े स्विचों में विस्तार करने का कार्य शामिल होगा ।